चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, सोना भी चमका

बिना जीएसटी 2,01,250 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई

नई दिल्ली, 18 दिसंबर. सर्राफा बाजार में गुरुवार को निवेशकों और कारोबारियों की नजरें उस वक्त ठहर गईं, जब चांदी ने इतिहास रचते हुए नया ऑल टाइम हाई बना लिया.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, चांदी के भाव में जोरदार उछाल देखने को मिला और यह बिना जीएसटी 2,01,250 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई. जीएसटी जोड़ने के बाद इसकी कीमत 2,07,287 रुपये प्रति किलो हो गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. सिर्फ चांदी ही नहीं, बल्कि सोने के भाव भी गर्माते नजर आए. 24 कैरेट सोना मामूली बढ़त के साथ 1,32,454 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वैश्विक संकेतों, डॉलर में उतार-चढ़ाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने कीमती धातुओं की कीमतों को सहारा दिया है. खास बात यह है कि इस साल चांदी और सोना दोनों

ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, जिससे बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है.

सर्राफा बाजारों में गुरुवार को चांदी ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए निवेशकों को चौंका दिया. आईबीजेए द्वारा जारी ताजा दरों के अनुसार, चांदी के भाव में एक ही दिन में 1,609 रुपये की तेजी दर्ज की गई और यह बिना जीएसटी 2,01,250 रुपये प्रति किलो पर खुली. जीएसटी सहित इसकी कीमत 2,07,287 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर माना जा रहा है.

> इस साल अब तक चांदी की कीमतों में कुल 1,15,233 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे यह निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक एसेट बनकर उभरी है. वहीं, सोने के भाव में भी मजबूती बनी हुई है. 24 कैरेट सोना 137 रुपये की तेजी के साथ 1,32,454 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. जीएसटी जोड़ने के बाद इसका भाव 1,36,427 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. बुधवार को सोना 1,32,317 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. कैरेट के हिसाब से देखें तो 23 कैरेट सोना 1,31,924 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,21,328 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 99,341 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.

पांच दिन की गिरावट से उबरा रुपया, 56 पैसे मजबूत

मुंबई, 18 दिसंबर. अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया पांच दिन की गिरावट से उबरता हुआ बुधवार को जबरदस्त उतार-चढ़ाव के बाद 55.75 पैसे मजबूत हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 90.38 रुपये का बोला गया. भारतीय मुद्रा इससे पहले पांच दिन में 106 पैसे टूटी थी. मंगलवार को यह 15.75 पैसे गिरकर 90.9375 अंक पर बंद हुई थी. रुपया आज 11.75 पैसे गिरकर 91.05 रुपये प्रति डॉलर पर खुला हालांकि खुलते ही इसने वापसी की और 89.9675 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ. हालांकि बाद में काफी हद तक नीचे आते हुए 90.38 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ.

एयरटेल पेमेंट्स बैंक में ईवी वॉलिट रिचार्ज शुरू

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर. एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड के साथ साझेदारी में एयरटेल थैंक्स ऐप पर भारत कनेक्ट (बीबीपीएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से ईवी वॉलिट रिचार्ज की सुविधा शुरू की है.

अब तक इलेक्ट्रिक वाहन के मालिकों को चार्जिंग का भुगतान करने के लिए चार्जिंग प्वाईंट ऑपरेटर द्वारा दिए गए वॉलिट का उपयोग करना पड़ता था. ईवी रिचार्ज श्रेणी के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक ग्राहकों को एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से सीधे अपने ईवी वॉलेट को टॉप अप करने में सक्षम बनाता है, जिससे यह प्रक्रिया सहज और तेज हो जाती है. कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि ग्राहकों को बस ऐप में लॉग इन करना है, बिल भुगतान के अंतर्गत ईवी रिचार्ज का चयन करना है, अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और रिचार्ज राशि दर्ज करनी है. भारत कनेक्ट सक्षम ऐप के माध्यम से सुरक्षित रूप से पुष्टि करके भुगतान करना है. और रिचार्ज की राशि तुरंत उनके वॉलिट में दिखाई देगी. यह सुविधा सभी एयरटेल थैंक्स ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है.

एयरटेल पेमेंट्स बैंक के कार्यकारी निदेशक गणेश अनंतनारायणन ने कहा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक में हम अपने ग्राहकों का दैनिक अनुभव बेहतर बनाने के लिए लगातार डिजिटल-फर्स्ट सॉल्यूशंस प्रदान करते हैं. हम ईवी वॉलिट रिचार्ज के माध्यम से देश में बढ़ते हुए ईवी परिवेश को सपोर्ट कर रहे हैं तथा यूजर्स को अपना वॉलिट तुरंत रिचार्ज करने का एक सरल तथा सुरक्षित तरीका प्रदान कर रहे हैं.

> यह डिजिटल बैंकिंग में नवाचार की दिशा में एक और कदम है. एनपीसीआई भारत बिलपे की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नूपुर चतुर्वेदी ने कहा, हमें ईवी वॉलिट रिचार्ज के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी करने की खुशी है. इससे देश के बढ़ते ईवी परिवेश को समर्थन मिलेगा. हम मिलकर ग्रीन मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य के लिए तैयार डिजिटल पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं.

शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव सेंसेक्स 78 अंक लुढ़का

मुंबई, 18 दिसंबर. घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को बड़ा उतार-चढ़ाव देखा गया और बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 77.84 अंक टूटकर 84,481.81 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी तीन अंक यानी 0.01 प्रतिशत उतरकर 25,815.55 अंक पर सपाट बंद हुआ.

बाजार में आज काफी उतार-चढ़ाव देखा गया. सुबह गिरावट में खुलने का बाद सेंसेक्स नीचे 84,238.43 अंक और ऊपर 84,780.19 अंक तक गया. बुधवार को यह 84,559.65 अंक पर बंद हुआ था. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.50 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.13 प्रतिशत की बढ़त में रहा.

मीडिया, ऑटो, रसायन, तेल एवं गैस और फार्मा समूहों के सूचकांकों में गिरावट रही जबकि आईटी, रियलिटी और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों के सूचकांक चढ़ गये. सेंसेक्स की कंपनियों में सनफार्मा का शेयर पौने तीन फीसदी के करीब टूट गया. टाटा स्टील और पावरग्रिड में भी एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट रही.

ओला इलेक्ट्रिक के शेयर फिर लुढ़के, निवेशक सतर्क

नई दिल्ली, 18 दिसंबर. इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. गुरुवार को शेयर बाजार में एक बार फिर ओला के शेयर दबाव में नजर आए और यह एनएसई पर करीब 4.29 फीसदी गिरकर 31.49 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया. इस ताजा गिरावट की बड़ी वजह कंपनी के प्रमोटर भाविश अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त हिस्सेदारी की बिक्री मानी जा रही है. बुधवार को भाविश अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक के करीब 4.2 करोड़ शेयर बेचकर लगभग 142 करोड़ रुपये जुटाए थे. इससे एक दिन पहले भी उन्होंने 2.6 करोड़ शेयरों की बिक्री की थी. लगातार हो रही इस प्रमोटर बिक्री ने बाजार में निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है.

पावरग्रिड और अफ्रीका 50 के बीच समझौता

- परियोजना के तहत 400 केवी लेसोस-लोसुक और 220 केवी
- 287 सब-स्टेशनों, 1.81 लाख सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन

गुरुग्राम, 18 दिसंबर. केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न सार्वजनिक उपक्रम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) ने अफ्रीका 50 के साथ केन्या में महत्वपूर्ण पारेषण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

इस परियोजना के तहत 400 केवी लेसोस-लोसुक और 220 केवी किसुमू-काकामेगा-मुसागा ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण किया जाएगा.

परियोजना की रियायती अवधि 30 वर्ष निर्धारित की गई है. समझौता पावरग्रिड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. आरके. त्यागी की उपस्थिति में संपन्न हुआ. इस अवसर पर केन्या सरकार के ऊर्जा और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. यह परियोजना अफ्रीका की पहली स्वतंत्र पारेषण परियोजना (आईटीपी) है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पावरग्रिड की पहली ऐसी परियोजना है, जो पूर्णत: प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल पर आधारित है.

यह परियोजना केन्या के राष्ट्रीय ग्रिड को सशक्त बनाएगी, बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाएगी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्रमुख लोड केंद्रों तक बिजली पहुंचाने में सहायक होगी. अफ्रीका 50 वित्तीय और क्षेत्रीय विशेषज्ञता प्रदान करेगा, जबकि पावरग्रिड अपने तकनीकी, संचालन और परियोजना प्रबंधन अनुभव का योगदान देगा. 15 दिसंबर 2025 तक पावरग्रिड 287 सब-स्टेशनों, 1.81 लाख सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों और 5.93 लाख एमवीए क्षमता का संचालन कर रहा है, जिससे उसकी वैश्विक तकनीकी क्षमता प्रमाणित होती है.

दवा बाजार पांच साल में 130 अरब डॉलर का होने की उम्मीद

2024-25 में देश के दवा निर्यात का मूल्य 30 .47 अरब डॉलर रहा

भारतीय दवाओं का निर्यात दुनिया के 200 से अधिक देशों में किया जाता है

नई दिल्ली, 18 दिसंबर. देश का घरेलू दवा बाजार अगले पांच साल में दोगुने से ज्यादा होकर 130 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद है. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने दवा निर्यात पर बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक दिवसीय चिंतन शिविर में एक वीडियो संदेश में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि देश का घरेलू दवा बाजार वर्तमान में लगभग 60 अरब डॉलर का आंका गया है. इसके 2030 तक लगभग 130 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र के आकार, गहराई और नवाचार क्षमता को दर्शाता है.

श्री अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2024-25 में देश के दवा निर्यात का मूल्य 30.47 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक है. यह वृद्धि मजबूत विनिर्माण आधार और बढ़ती वैश्विक पहुंच के कारण संभव हुई. केंद्रीय वाणिज्य विभाग द्वारा भारतीय औषधि निर्यात संवर्धन परिषद (फार्मेक्सिल) के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं, नियामकों, उद्योग प्रतिनिधियों, छोटे तथा मध्यम उद्यमों सहित निर्यातकों, विदेशों में भारतीय मिशनों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया. प्रतिभागियों ने देश के दवा निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया. वाणिज्य सचिव ने बताया कि मात्रा के आधार पर आज भारत मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा दवा विनिर्माता है. देश में तीन हजार से अधिक कंपनियां, 10,500 विनिर्माण इकाइयां और 60 चिकित्सीय क्षेत्रों में 60,000 से अधिक जेनेरिक ब्रांड हैं. भारतीय दवाओं का निर्यात दुनिया के 200 से अधिक देशों में किया जाता है, जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक निर्यात कड़े नियामकीय मानकों वाले देशों को जाते हैं.

28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की होगी एक पहचान

ग्रामीण समुदायों के प्रति देखभाल, सहयोग और सहायता का संदेश देता है

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर. राज्य स्तर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण के बाद सरकार ने अब उनके लिए नया लोगो जारी किया गया है.

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि यह लोगो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ मिलकर जारी किया गया है. यह देश में काम कर रहे सभी 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए एकीकृत ब्रांड पहचान स्थापित करेगा. इससे उनकी पहचान और विजिबिलिटी मजबूत होगी. इस लोगों में एक लौ है जो तीन स्तरों से मिलकर बनी है. मंत्रालय ने बताया कि यह लौ ऊष्मा, ज्ञान और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने का संकेत देती है. यह लौ ऊपर की तरफ जा रही है जो प्रगति का प्रतीक है और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में विकास, उन्नति तथा प्रगति को दर्शाता है. इसमें हाथ भी दिख रहा है जो संरक्षण और पोषण का प्रतीक है.

यह ग्रामीण समुदायों के प्रति देखभाल, सहयोग और सहायता का संदेश देता है. कहा गया है कि आरआरबी के लोगो के रंग भी उनके उद्देश्यों को दर्शाने के लिए चुने गये हैं. गहरा नीला रंग वित्त और विश्वास का प्रतीक है, जबकि हरा रंग जीवन और विकास का संकेत देता है, जो ग्रामीण भारत की सेवा के उनके मिशन को प्रतिबिंबित करता है.

टैली सॉल्यूशन्स ने पेश किया टैलीप्राइम 7.0

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर. देश की अग्रणी बिजनेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कंपनी टैली सॉल्यूशन्स ने टैलीप्राइम 7.0 पेश किया है जिसे विशेष रूप से एमएसएमई को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. कंपनी ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि टैलीप्राइम 7.0 एकीकरण को बेहतर बनाता है, स्मार्ट ऑटोमेशन और मजबूत डेटा सुरक्षा के साथ व्यवसायों को सहज अनुभव प्रदान करता है. भारतीय स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक के साथ बेहतर एकीकरण के जरिये अब व्यवसाय सीधे टैलीप्राइम के भीतर भुगतान कर सकते हैं.

ईपीएफ योजना में शामिल होने का छ: महीने का मौका

नई दिल्ली, 18 दिसंबर . कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं से अपील की है कि वे ईपीएफ योजना से छूट गए पात्र कर्मचारियों को स्वेच्छा से योजना में शामिल करें.

इसके लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी नामांकन योजना -2025 के तहत छह महीने की विशेष अनुपालन अवधि घोषित की है, जो नवंबर 2025 से शुरू होगी. इस योजना के तहत नियोक्ता 1 जुलाई 2017 से 31 अक्तूबर 2025 के बीच कवरेज से बाहर रह गए पात्र कर्मचारियों को पुन: नामांकित कर सकते हैं और पिछली अनियमितताओं को नियमित कर सकते हैं. -2025 के प्रावधानों के अनुसार, जिन मामलों में कर्मचारियों का अंशदान पहले नहीं काटा गया था, वहां नियोक्ता को केवल अपना अंशदान, धारा 7क्यू के तहत ब्याज, लागू प्रशासनिक शुल्क और 100 रुपये का सीमित दंड जमा करना होगा. इसे ईपीएफओ की तीनों योजनाओं के तहत पूर्ण अनुपालन माना जाएगा.

समाचार विशेष

मुस्लिम लीग के किले पर लगातार तीसरी बार दबदबा

कासरगोड. केरल के निकाय चुनाव दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के लिए नए दरवाजे खोल रही है. पहले पार्टी ने राजधानी तिरुवनंतपुरम में 15 सीटों पर जीत हासिल की, कोझिकोड में सीटें लगभग दोगुनी की, कोल्लम में छह सीटें हासिल की और फिर कासरगोड में भी अपने दूसरे स्थान को बरकरार रखा.

कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने यहां के स्थानीय निकाय चुनाव में 39 में से 24 सीटें हासिल कीं तो लेफ्ट पार्टी ने दो सीटें जीतीं जो कि पिछली बार के मुकाबले दोगुना है. वहीं एनडीए ने 12 सीटों पर कब्जा किया. बता दें कि पिछले चुनाव में एनडीए के पास 14 सीटें थीं. कासरगोड निकाय में यूडीएफकी 24 में से 23 सीटें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मिली हैं. दरअसल यहां बीते कई वर्षों से यूडीएफऔर एनडीए के बीच कड़ी टक्कर रही है.

पिछले कई दशकों से कासरगोड में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपना वर्चस्व बनाया हुआ है. केरल के बाकी हिस्सों के उलट कासरगोड में वामदलों की मौजूदगी लगभग न के बराबर है. हालांकि पिछली बार जीते एक सीट के मुकाबले उन्हें इस बार दो सीटें जरूर मिली हैं. लगभग 38 फीसद मुस्लिम आबादी वाले इस जिले में लीग 1965 से ही जीतती चली आई है. कासरगोड में पहले 38 वार्ड थे जिनकी संख्या अब 39 हो गई है.

हालांकि पिछले तीन चुनावों में यहां के दक्षिण क्षेत्र में बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और कांग्रेस.मुस्लिम लीग के लिए एक चुनौती के रूप में उभरी है पर अब तक जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ही जीतती आ रही है. यही कारण है कि कांग्रेस यहां अपनी सहयोगी मुस्लिम लीग को उतारती रही है.

जबकि निकाय की जिन सीटों पर मुसलमानों की आबादी कम है वहां अब बीजेपी को जीत हासिल हो रही है.

कासरगोड का बदलता समीकरण

निकाय चुनाव में कासरगोड में प्रभुत्व इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का ही रहा है जो 70 के दशक से अब तक यूडीएफका एक स्थायी और अहम सहयोगी बना हुआ है. हालांकि यहां की राजनीति में बीजेपी के आने से पहले तक यहां मुकाबला साफ तौर पर यूडीएफ ;मुस्लिम लीग, कांग्रेस और वामदल के बीच रहा है. विधानसभा चुनावों की बात करें तो यहां की उदुमा, कान्हांगड़, होसदुर्ग सीटों पर लेफ्ट ने लंबे समय तक जीत दर्ज किया. इन इलाकों में भूमि सुधार आंदोलन, ट्रेड यूनियन और किसान संगठन मजबूत रहे. यहीं से कासरगोड की पहचान लेफ्ट प्रभाव वाले जिले के रूप में बनी. यहां के किसान और खेतीहर मजदूरोंए बीड़ी मजदूरए दलित और आदिवासी आबादी में और ग्रामीण इलाकों में लेफ्ट ने अपना दबदबा बना कर रखा. यह स्थिति 80-90 के दशक तक बनी रही.

कुर्मी कार्ड से भाजपा ने चली चुनावी चाल

पिछड़े समाज पर मजबूत होगी पकड़

लखनऊ. भाजपा ने उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज से पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आने वाले चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है. यह निर्णय केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुभवों से निकली सोची-समझी रणनीति माना जा रहा है.

सपा ने पिछले लोक सभा चुनाव में कुर्मी समाज के 10 उम्मीदवार उतारे थे उनमें से सात जीतकर संसद पहुंचे हैं. कुर्मी समाज न सिर्फ संगठित है, बल्कि सही राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने पर निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखता है. इसी सियासी संदेश को भाजपा ने गंभीरता से लेते हुए कुर्मी कार्ड चलकर 2027 के विधान सभा चुनाव की चाल साधने की कोशिश की है.

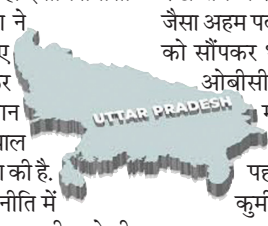

प्रदेश की राजनीति में कुर्मी समाज की आबादी भले ही आठ प्रतिशत आंकी जाती हो, लेकिन 70 से 80 विधान सभा सीटों पर इनका सीधा प्रभाव माना जाता है. खासकर पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्रों में कुर्मी मतदाता कई सीटों पर जीत-हार का रुख तय करते हैं. प्रदेश अध्यक्ष जैसा अहम पद कुर्मी समाज के नेता को सौंपकर भाजपा ने गैर-यादव ओबीसी वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश की है. इससे पहले भी भाजपा का कुर्मी कार्ड वर्ष 2022 में सफल हुआ था, उस समय स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे और भाजपा की पांच वर्ष सरकार रहने के बावजूद 403 में से 255 सीटें मिली थीं.

> पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह कदम अपना दल (एस) के पारंपरिक कुर्मी प्रभाव को भी संतुलित करने की दिशा में देखा जा रहा है. भाजपा चाहती है कि कुर्मी वोट बैंक केवल गठबंधन तक सीमित न रहे, बल्कि संगठन के भीतर स्थायी रूप से जुड़कर पार्टी की कोर राजनीति का हिस्सा बने. इस नियुक्ति के जरिए भाजपा ने सामाजिक संतुलन का भी संदेश दिया है.

कर्नाटक का मामला नहीं सुलझा

नई दिल्ली. कांग्रेस पार्टी कर्नाटक का मामला नहीं सुलझा पा रहा है. रविवार को दिल्ली में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों आए थे. दोनों की मुलाकात कांग्रेस आलाकमान के नेताओं से हुई लेकिन बताया जा रहा है कि नेतृत्व का मामला नहीं सुलझाया जा सका.

देर शाम को मुख्यमंत्री वापस लौट गए क्योंकि बेलगावी में विधानसभा का सत्र चल रहा है. लेकिन उप मुख्यमंत्री शिवकुमार दिल्ली में रूके. यह जानकारी नहीं है कि रविवार की रात को उनकी किन नेताओं से मुलाकात हुई और उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर क्या चर्चा हुई. लेकिन यह हकीकत है कि कर्नाटक में अब भी मामला तलवार की धार पर है.

गौरतलब है कि पार्टी आलाकमान के कहने पर सिद्धारमैया और शिवकुमार ने एक दूसरे को अपने घर नाश्ते पर बुलाया और मीडिया के सामने एकजुटता की तस्वीर दिखाई. लेकिन अंदरखाने सब कुछ पहले जैसा चल रहा है.

बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते शिवकुमार के समर्थक विधायकों ने एक डिनर पार्टी का आयोजन किया. इसमें जो चर्चा हुई उसका लब्बोलुआब यह है कि शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. उनके समर्थक एक मुस्लिम विधायक ने बाद में सामने आकर कहा कि छह या नौ जनवरी को कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा.

> उनका कहना था कि सिद्धारमैया सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का देवराज अर्स का रिकॉर्ड तोड़ देंगे उसके बाद उनको हटा दिया जाएगा. अगर ऐसा होता है तो शिवकुमार 14 जनवरी के बाद किसी दिन शपथ लेंगे. हालांकि दूसरी ओर मुख्यमंत्री के बेटे यतींद्र ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया है कि कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है. यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आलाकमान की ओर से सिद्धारमैया को क्या निर्देश दिया जाता है और वे उसका कितना पालन करते हैं.

विशेष | प्रियंका के साथ 'सीक्रेट मीटिंग' ने बढ़ाई हलचल

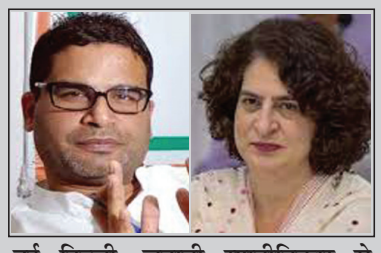

कांग्रेस ज्वाइन करेंगे प्रशांत किशोर?

नई दिल्ली. चुनावी रणनीतिकार से सियासतदान बने प्रशांत किशोर ने हाल ही में इंडियन नेशनल कांग्रेस की महासचिव और केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की. इस मुलाकात ने पटना से दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में जोरदार अटकलों को जन्म दिया है. सूत्रों का दावा है कि यह मुलाकात उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित पांच राज्यों में 2027 के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में हुई थी.

हालांकि, न तो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज और न ही कांग्रेस पार्टी ने इस मुलाकात के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है. यह मुलाकात बिहार विधानसभा चुनावों के लगभग एक महीने बाद हुई. जिसके चलते इस मीटिंग को एक सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार से कहीं ज्यादा माना जा रहा है. यह मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किशोर लंबे समय से कांग्रेस के मुखर आलोचक रहे हैं. जबकि अब पार्टी में उनके संभावित प्रवेश को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बिहार विधानसभा चुनावों में जन सुराज पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. किशोर की पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही. उसके 238 में से 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई.

साझा संकट की वजह से मुलाकात!- इस नतीजे ने किशोर की रणनीतिक विश्वसनीयता और भविष्य की राजनीतिक दिशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. दूसरी ओर कांग्रेस का प्रदर्शन भी खराब रहा. 2020 की 19 सीटों की तुलना में उसे 61 में से सिर्फ छह सीटें मिलीं. इस साझा राजनीतिक संकट ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए ज़मीन तैयार की है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं हो सकती, बल्कि संभावनाओं को तलाशने की कोशिश भी हो सकती है. कांग्रेस संगठन नई ऊर्जा और रणनीतिक दिशा की तलाश में है. दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को एक राष्ट्रीय मंच की ज़रूरत महसूस हो रही है. यही वजह है कि इस मुलाकात को कांग्रेस में उनके संभावित प्रवेश का पहला संकेत माना जा रहा है, भले ही इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई हो. प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के बीच रिश्ता नया नहीं है. चाहे रणनीतिकार के तौर पर हो या राजनीतिक सलाहकार के तौर पर, किशोर पहले भी कांग्रेस नेतृत्व के साथ बातचीत कर चुके हैं. 2020 के बिहार चुनाव अभियान के दौरान, उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताई थी.